

केवराजी एकरण कमाळ
18-2-11-2011

1/2/11

पुस्तकालय, अहमदनगर

साथमिच लघु वनउपलब्ध
उद्दकारि अरुधक मिश्रसौनी
साथमिच लघु वनउपलब्ध
साथमिच लघु वनउपलब्ध
साथमिच लघु वनउपलब्ध

केवराजी एकरण कमाळ
18-2-11-2011

बनास

अहमदनगर, अहमदनगर

1. केवराजी एकरण कमाळ पुस्तकालय
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
2. केवराजी एकरण कमाळ पुस्तकालय
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर

दिनांक 18-2-11-2011
प्रा. दिवाकर कावितर पणवणे
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर
अहमदनगर अहमदनगर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगम 2114 दा/14

जिला - दतिया

स्थान तथा
दिनांक

अर्थवाही तथा मंद

पक्षकारी एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

22-7-14

प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/बी-121/2013-14 में पारित रथगन आदेश दिनांक 10-7-14 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर द्वारा उनके समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपने पूर्व के आदेश दिनांक 31-5-14 का क्रियान्वयन अन्य आदेश तक के लिए रथगित किया गया है ।

2- प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक तथा अनावेदक क्र. 2 म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं रथगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर मनन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत आवेदक को शासकीय उचित मूल्य की दुकान आवंटित किए जाने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-5-14 को दिए गए हैं । इस आदेश को उन्होंने सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर की ओर से संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आवेदक को बिना सुने संहिता की धारा 52 के तहत अन्य आदेश तक रथगित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल आदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत पारित किया गया है नाकि संहिता के प्रावधानों के तहत एसी स्थिति में सर्व सहकारी संस्था, दुर्गापुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही उक्त अधिनियम के तहत ही करना चाहिए था । अतः अधिवक्ता न्यायालय द्वारा पारित आलाच्य आदेश इसी स्तर पर निरस्त करने हुए अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाने हैं कि वे सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के प्रावधानों के प्रकाश में उभयपक्षों को सुनकर करें । उक्त निर्देश के साथ यह विवरणों निराकृत की जाते हैं । आदेश को पारित करके अतिरिक्त प्रमाणों के साथ म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही रथगित किया गया है ।


सदस्य